

नदबर्ई में बारिश बनी आफत

नदबर्ई, 22 सितम्बर (निस)। प्रदेश में गुरुवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तेज अंधड़ व बारिश किसानों के लिए आफत बन गई।

ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बारिश होने से किसानों के खेत में रखी ज्वार व बाजरे की फसल नष्ट हो गई है। तेज बारिश से फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों के चेहरे मायूस नजर आए।

ग्राम पंचायत गगवाना के गांव चैनपुरा, बसईया, गगवाना के किसानों की फसलें बारिश की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गईं। ग्राम पंचायत गगवाना के सरपंच हरस्वरूप शर्मा ने सरकार से किसानों की खराब हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्वार व बाजरा की फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को पशुओं के चारे को लेकर भी चिंता सताने लगी। बारिश से पहले जहां किसान फसल को देखते हुए अपनी खुशी जता रहे थे, वहीं अब बारिश में फसल खराब होने पर मायूस बने हुए हैं।

दूसरी ओर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गंग ने क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण खरीफ की फसलों को हुए

- भारी बारिश से ज्वार व बाजरे की फसल बर्बाद हो गई।
- गगवाना के सरपंच हरस्वरूप शर्मा ने सरकार से फसल खराबे के मुआवजे की मांग की।

नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया एवं आपदा प्रबंधन व सहायता मंत्री गोविन्दराम मेघवाल को भी अलग-अलग पत्र लिखकर अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलों के हुये नुकसान की किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की भी मांग की है।

डॉ. गंग ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन को निर्देश दिये कि, वर्षा के कारण खरीफ की खेतों में खड़ी अथवा कटी हुई फसलों को हुए नुकसान के लिए तत्काल विशेष गिरदावरी शुरू कराये ताकि फसल खराबे वाले किसानों को नियमानुसार मुआवजा मिल सके।



नदबर्ई में अचानक तेज बारिश के कारण खेत में सूखने के लिए पड़ी बाजरे की फसल भीग गई। ज्वार व बाजरे की फसल को हुये नुकसान के चलते किसानों के चेहरों पर भारी मायूसी नजर आई।

उदयपुर से भी दो संदिग्ध गिरफ्तार

उदयपुर, 22 सितम्बर (कास)। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने देश भर में पी.एफ.आई. के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान इस संगठन से जुड़े उदयपुर के दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एन.आई.ए. ने अभियान के दौरान उदयपुर के खांजीपीर

- एन.आई.ए. ने शहर के खांजीपीर क्षेत्र से ये गिरफ्तारियां की हैं।

- एन.आई.ए. को पता चला है कि, ये दोनों व्यक्ति टैरर फंडिंग व टैरर ट्रेनिंग में लिप्त रहे हैं।

क्षेत्र से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों को पहचान मोहम्मद इरफान व मोहम्मद सलीम की रूप में उजागर की गई है। सूत्रों से पता चला कि, एन.आई.ए. को टैरर फंडिंग व कैप लगा कर बच्चों को टैरर ट्रेनिंग देने के इनपुट भी मिले हैं। इस अभियान में एन.आई.ए. के साथ साथ इन्फोसैफ डायरेक्टरेट (ई.डी.) की टीम भी शामिल है। जो प्रदेश के जयपुर, कोटा, बाण, उदयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर पी.एफ.आई. से जुड़े स्थानों पर दबीश दे रही है।

ओडिशा में कार से एक किंवदंती चांदी की ईंटें व कैश मिला

कटक, 22 सितम्बर (वार्ता)। ओडिशा के कटक में आबकारी अधिकारियों की टीम ने टांगी टोल गेट के पास एक कार से 100 किलोग्राम से ज्यादा वजन की 47 चांदी की ईंटें, 19 पैकेट में चांदी के गहने और 14 लाख रुपये नकद जब्त किए।

आबकारी विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधित गांजा की तस्करी की सूचना के आधार पर कार को रोका गया। तलाशी के दौरान उसमें छुपाकर रखी गयी चांदी की ईंटें, गहने, कुछ दस्तावेज और नकदी बरामद किये गये। चांदी की ईंटें कार्नाज में लपेटकर रखी गई थीं। आबकारी अधिकारियों ने वाहन चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पड़ताछ की। उन्होंने आशंका जतायी है कि इस वाहन को सोने और चांदी की तस्करी करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा संभवतः इसका उपयोग पहले भी तस्करी में किया गया होगा।

जयपुर में पीएफआई के कार्यालय पर एनआईए ने छापा मारा

जयपुर, 22 सितम्बर। पाँपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) और इससे जुड़े लोगों, संस्थानों पर पूरे देश में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जयपुर में बुधवार देर रात को जयपुर में लाल कोठी के पास पी.एफ.आई. कार्यालय में सर्च किया गया।

इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज व अन्य सामान जब्त किये गये हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार राज्य के पांच शहरों में भी एन.आई.ए. से बुधवार देर रात से सुबह तक सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की है। इस दौरान जयपुर में एमडी रोड पर स्थित प्रदेश स्तरीय कार्यालय पर भी एन.आई.ए. ने रेड डाली।

सुबह नौ बजे तक चली रेड में संदिग्ध दस्तावेज, हार्ड डिस्क, झंडे, प्रतिबंधित साहित्य और किताबें मिली हैं। बताया जा रहा है कि, इस रेड में ईडी के अफसर भी साथ हैं। इस कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया है। सी.आर.पी.एफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही यह रेड की गई है। जयपुर पुलिस को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जयपुर में अभी

- पुलिस सूत्रों के अनुसार, लाल कोठी के पास स्थित कार्यालय से सर्च के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज व अन्य सामान जब्त किया।

3 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि, दो साल पहले भी ईडी ने जयपुर में पी.एफ.आई. के दफ्तर पर छापा मारा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पी.एफ.आई. के खिलाफ टैरर फंडिंग और कैम्प चलाने के इनपुट को मिले हैं। उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार दो दिन से एन.आई.ए. की टीमों राजस्थान के कोटा, वारां, उदयपुर, अजमेर और जयपुर में कार्रवाई करने में जुटी हैं।

उधर एन.आई.ए. की कार्रवाई के विरोध में जयपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच संपादन से जुड़े कई बड़े नेता भूमिगत हो गए हैं। उनकी सर्च के लिए एनआईए लगातार प्रयासरत है।

शिंजो आबे

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 27 सितंबर को जापान की एक दिन की यात्रा पर जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां नियमित ब्रीफिंग में संवाददाताओं को यह जानकारी दी और कहा कि मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। आबे की आठ जुलाई को जापान के नारा शहर में उनके प्रचार भाषण के दौरान एक 41 वर्षीय शख्स ने बहुत नजदीक से गोली मार कर हत्या कर दी थी। वह

- शिंजो आबे की अंत्येष्टि में शामिल होने जापान जायेंगे प्र.मंत्री मोदी।

दो बार जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देश में असाधारण घटना के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कई विदेशी राजनेता भी शामिल होंगे जिनमें मोदी एवं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की संभावना के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। चूंकि मोदी की यात्रा एक दिन की होगी और समय की कमी होगी।

एन.आई.ए ने आधी रात के बाद 11 राज्यों में एक साथ पी.एफ.आई. के ठिकानों पर छापे मारे

मुख्य रूप से पी.एफ.आई. को विदेशी सहायता प्राप्त होने के प्रमाण के आधार पर ये छापे डाले गये

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। पाँपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) ने देश के 11 राज्यों में एक साथ छापे मारे। पूरे देश भर में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एन.आई.ए. के ऑपरेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस ऑपरेशन के लिए गृह मंत्रालय में कमांड सेंटर बनाया गया था। 6 कंट्रोल रूम के जरिए इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई। यह पूरा ऑपरेशन सुबह 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चला। इस दौरान एन.आई.ए. के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे।

छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन में एन.आई.ए. के 200 स्टाफ शामिल थे। के 4 आई.जी., 1 ए.डी.जी. और 16 एस.पी. इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे। इसका कमांड कंट्रोल सेंटर गृह मंत्रालय में था। पी.एफ.आई. से जुड़े संदिग्धों के सभी डोजियर छापे वाली

- देश भर में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऑपरेशन के लिए गृह मंत्रालय को कमाण्ड सेंटर बनाया गया।

- यह पूरा ऑपरेशन रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चला। इस दौरान एन.आई.ए. के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन में एन.आई.ए. के 200 स्टाफ शामिल थे।

- पी.एफ.आई. की केरल इकाई ने इन छापों के खिलाफ आज शुक्रवार को बंद एवं विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

टीम को दिए गए सभी संदिग्धों की रेकी पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से की जा रही थी। छापों में 200 से अधिक मोबाइल, 100 से अधिक लैपटॉप जब्त किए गए। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज, विजन दस्तावेज, नामांकन फॉर्म, बैंक डिटेल्स भी जब्त किए गए हैं।

राज्य सरकार से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख के. सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि पी.एफ.आई. द्वारा पूर्व में आहूत सभी हड़ताल में दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राधिकारियों को लोगों के जीवन और संपत्ति की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पी.एफ.आई. बाहुबल के जरिये आतंकवाद के मामलों से निपटने की कोशिश कर रहा है और उसके नेतृत्व से यह ध्यान रखने को कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है न कि एक धार्मिक राष्ट्र। सुरेंद्रन ने एक बयान में कहा कि अनावश्यक हड़ताल के खिलाफ राज्य न्यायालय के कड़े रूख के बावजूद उच्च में वामपंथी सरकार वोट बैंक पर नजर रखते हुए पी.एफ.आई. के प्रति नरम रूख दिखा रही है।

एक हिजाब पर दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अब तमिलनाडू के रामनाथपुरम में पिछले दिन वही हिजाब मुद्दा सामने आया, जहां स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने दो बालिकाओं द्वारा हिजाब पहने जाने पर आपत्ति जताई तथा हिजाब पहनने वाली छात्राओं से कह दिया कि कक्षा-कक्षा में प्रवेश करने से पहले, वे अपने स्कॉर्फ (हिजाब) को उतार कर अपने-अपने बैगों में रख लिया करें।

अगर यह घटना दक्षिण में हिन्दुत्व की प्रयोगशाला में, यानी कर्नाटक में हुई होती तो अधिकारियों ने प्रधानाध्यापिका का समर्थन किया होता। लेकिन तमिलनाडू में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां हिजाब पर रोक नहीं है।

यह मुद्दा तुरंत ही समाप्त कर दिया गया। राज्य के शिक्षा विभाग ने संस्था प्रधानों तथा गलती करने वाली स्कूल प्रधानाध्यापिका को स्पष्ट कर दिया कि हिजाब पहनने तथा नहीं पहनने का चुनाव पूरी तरह से छात्राओं की मर्जी है। विभाग ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि विद्यालय-प्रशासन ऐसे मामलों में

हस्तक्षेप नहीं करेगा। दो पड़ोसी राज्यों-तमिलनाडू तथा कर्नाटक की सरकारों की इस मुद्दे पर सोच एवं संबंधित प्राथमिकताओं का विरोध पूरी तरह तथा साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों सरकारों को बिल्कुल ताजा कदमों और पहलों पर नजर डालें तो हम पायेंगे कि तमिलनाडू

‘द तिरूमला...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमीर धर्मस्थल की व्यवस्था देखा है। वैटिकन के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेना शुरू कर दिया था। देश भर के विभिन्न मंदिरों में अब कर्मोवेश यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। रोजगार के काम काज को आसान बनाने और आम समस्याओं के हल के लिए टैक्नॉलजी के इस्तेमाल के प्रति रूझन के चलते टी.टी.डी. ने एक मोबाइल ऐप्लीकेशन तैयार की है जो देश भर से आने वाले अलग-अलग भाषा वाले व्यक्तियों को भाषा की समस्या दूर कर देगी। सोमवार और मंगलवार को इस ऐप का सफल ट्रायल हुआ।

ऐप का नाम है ‘द तिरूमला गाइड’ जो यहां आने वाले भक्तों के लिए फायदेमंद है। इसमें भक्तों की समस्त आवश्यक जानकारी, जैसे गैस्ट हाउस, लड्डू, काउंटर, वैकुण्ठ न्यू कॉम्प्लेक्स, सतकंता ऑफिस, हॉस्पिटल, म्यूजियम, पुलिस, प्रशासन व अन्य सेवाओं की जानकारी दी गई है। टी.टी.डी. को भरोसा है यह सभी के लिए मददगार होगा।

‘निर्धन सवर्णों को दिया गया...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टी. का आरक्षण आठवें दशक में प्रवेश कर चुका है, जबकि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण जनरल कैटेगरी के कमजोर तबके में आर्थिक मजबूती आने और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार आने के साथ ही कमजोर पड़ जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने सुझाया कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण चिरस्थायी रहने वाला नहीं है।

इस तर्क का जवाब देते हुए ई.डब्ल्यू.एस. के 10 प्रतिशत आरक्षण में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए था अर्दानीं जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि इस प्रकार की समझ एक ऐसी स्थिति को और ले जाता, जहां एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन, चारों वर्गों को ई.डब्ल्यू.एस. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरवली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्म एम.आई.रेंड, जयपुर फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, 2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आर्यद, उदयपुर फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाउस, हट्टमन हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स: 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोलसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोलसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

प्रतिशत जनरल से में 2.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता। अर्दानीं जनरल ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति से एस.सी./एस.टी. तथा ओ.बी.सी. को दिये जा रहे 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का अतिक्रमण हो जायेगा, जिसे 1992 में इन्द्रा साहनी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की बैच ने शुरु किया था।

यह दलील देते हुये कि असमानों को समान नहीं माना जा सकता, अर्दानीं जनरल ने उन जबरदस्त लार्कों का उल्लेख किया, जो एस.सी./एस.टी. को मिलते हैं। उन्होंने पंचायत, स्थानीय निधाय, राज्य-विधायिका तथा लोकसभा में इन्हें मिल रहे आरक्षण का उल्लेख किया।

अर्दानीं जनरल ने कहा कि जहां तक ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण का प्रश्न है यह सिर्फ शिक्षा व सरकारी नौकरी में ही लागू होगा तथा गरीब आबादी

की आर्थिक स्थिति सुधरने पर वे इस आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही या और कुछ बताया जा सकता है लेकिन यह आरक्षण संसद की समझ में लाया गया था तथा इस बारे में सांख्यिकीय आँकड़े नहीं दिये गये थे।

एक और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा वर्तमान यात्रा यू.पी. में सिर्फ दो दिन रहेगी इसलिए एक पृथक यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे राज्य को कवर किया जाएगा।

वर्तमान यात्रा दक्षिण से उत्तर में करमीर तक की है। उन्होंने कहा पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्वी राज्यों, गुजरात और पूर्वांचल राज्यों को छोड़ दिया जाएगा।

‘मैं किसी के नाम की न चर्चा...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाने के फार्मूले पर भी बात हो रही है और यदि ऐसा हुआ तो इस दौड़ में सबसे आगे गोविंद सिंह डोटोसरा और शांति धारीवाल का नाम बताया जाता है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि, प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जाएगा इसके लिए महेश जोशी का नाम लिया जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस में जब तक फैसला होकर लागू नहीं हो जाए तब तक नामों की चर्चाओं के कयास लगे रहते हैं।

इससे पहले राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, यह एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रणाली है। जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वे एक ऐतिहासिक स्थान ले रहे हैं। एक ऐसा स्थान जो भारत के एक विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। कांग्रेस अध्यक्ष को विचारों के एक समूह, एक विश्वास प्रणाली और भारत के एक दृष्टिकोण का

प्रतिनिधित्व करना होगा।” मीडिया की ओर से, पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि, जो हालात राजस्थान के अंदर हैं, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा और देखेगा कि विधायकों की क्या भावना है। यह ध्यान रखना होगा कि, हम अगला चुनाव जीतें, क्योंकि हम कांग्रेस के पास बड़ा राज्य राजस्थान ही है। हमारे लिए यह फैसला बहुत नाजुक फैसला भी होगा और बहुत सोच-समझकर लेना पड़ेगा।” इसी के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि, आज तक इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि जो प्रश्न उठते हैं, उसी आधार पर हम लोग भी फैसला करेंगे।

गहलोत ने कहा कि, राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विधायक पार्टी की भूमिका में कांग्रेस में फिर से जान डालने के लिए काम करना है, फिर आप दो पद कैसे रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक व्यक्ति एक पद लागू नहीं होता, फिर भी

अध्यक्ष बनने वाले को सोचना होगा कि वह दो पद कैसे रखेगा, वह अध्यक्ष पद को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।

‘जो फैसला...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बसपा छोड़कर दूसरी बार कांग्रेस के साथ आने वाले ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि हाईकमान जिसे सीएम बनाए वह मंजूर होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिसे भी मुख्यमंत्री बना दें, हम उस फैसले के साथ हैं। अगर भरोसीलाल जाटव को भी सीएम बनाएंगे तब भी हम साथ हैं।

बसपा से कांग्रेस में आने वाले राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि कांग्रेस में जो भी फैसले होते हैं, उसमें हाईकमान का फैसला मान्य होता है। कम से कम हम छह विधायक को ग्रुप सिक्स में हैं, उनकी गारंटी है कि वह सभी हाईकमान के साथ हैं।

आखिर ऊंट पहाड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं, ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि सचिन के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है।

कल दिग्बिजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

यही बात आज राहुल ने दोहराई थी। कल सोनिया गांधी के साथ हुई मीटिंग में, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कह दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना ही होगा तथा इस बात का निर्णय नेतृत्व ही करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

कल सुबह गहलोत शिरडी रवाना हो जायेंगे। रोचक बात यह है कि इस ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ में सचिन पायलट, अशोक गहलोत के कुछ कदम आगे ही दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी से मिलने के लिये केरल जाने से पहले,

सचिन सोनिया गांधी से मिले थे उनके साथ सारी स्थिति पर चर्चा की थी। केरल पहुंचने के बाद, वे पूरे दिन राहुल के साथ पद यात्रा करते रहे तथा उनके साथ चर्चा करते रहे।

अशोक गहलोत, जो जयपुर में अपने विधायकों से कह रहे थे कि इस साल का बजट वे ही पेश करेंगे, सोनिया गांधी से मिलने एक दिन दूर से पहुंचे थे तथा राहुल गांधी से मिलने में भी उनसे एक बार पुनः देर हो गई थी। और गहलोत के इस झॉंसे की असलियत भी सामने आ गई है कि सरकार गिर जायेगी।

दरअसल, बसपा नेता राजेन्द्र गुड़ा ने कह दिया है कि जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, वे उस का समर्थन करेंगे।

गहलोत ने नेतृत्व को एक प्रकार की धमकी दे दी थी कि अगर वे हटायें जाते हैं तो निर्दलियों तथा बसपा द्वारा समर्थन वापस ले लिये जाने से सरकार गिर जायेगी।